अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक लागू करना - संबंधित मुद्दे और चुनौतियां *

के.सी. चक्रवर्ती

डॉ. नरेश चंद्र, प्रधानाचार्य, बिड़ला कॉलेज, भूतपूर्व प्रो वाइस चान्सलर, मुंबई विश्वविद्यालय, डॉ. श्याम अग्रवाल, प्रसिद्ध नेत्र शल्यचिकित्सक, श्री एम.एम. चितले, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अध्यक्ष, राष्ट्रीय लेखाकरण मानक परामर्शदात्री समिति, श्री. यू. वेंकटरामन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी - करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट और पूर्णकालिक निदेशक, एमसीएक्स-एसएक्स, पीडीएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऐण्ड एकोनामिक्स के प्रधानाचार्य तथा प्रिय छात्रगण, डॉ. एन.एन. पाण्डेय, प्रो.डी.एम. काढ़ी, संयोजक, अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगण, देवियो और सज्जनो। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक विषय पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह एक ऐसा प्रासंगिक विषय है जो काफी समय से मानक निर्धारित करने वालों, सरकारी अधिकारियों और विनियामक संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। इस विषय में मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखूंगा।

वित्तीय विवरणों को पढ़ना

2. मैं अपनी बात वाणिज्य और लेखाकरण के अत्यंत प्रारंभिक और मौलिक क्षेत्र - 'किसी वित्तीय विवरण को कैसे पढ़ा जाए'- से आरंभ करूंगा। किसी साधारण आदमी के लिए वित्तीय विवरणों के अंतर्गत तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे शामिल होंगे। लेकिन तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे में दी गई संख्याओं से किसी पाठक को किसी संस्था की सही तसवीर तब तक ज्ञात नहीं हो सकती जब तक वह लेखाओं से संबंधित टिप्पणियों, नकदी प्रवाह-विवरणों और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में दी गई, उनसे जुड़ी शर्तों इत्यादि को ध्यान से न पढ़े तथा संबंधित उद्यम द्वारा अपनायी गयी लेखाकरण नीतियों को न समझे। कुछ मामलों में किसी संस्था का बेहतर चित्र प्राप्त करने के लिए अनुपात-विश्लेषण, रुझान विश्लेषण और उसी उद्योग की दूसरी संस्थाओं से उसकी तुलना की जा सकती है। किसी व्यक्ति को सही निर्णय पर पहुंचने के लिए इन सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक होगा।

3. वित्तीय विवरण का उद्देश्य वित्तीय स्थिति, किसी संस्था के कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह के संबंध में ऐसी सूचना प्रदान करना है जो वित्तीय निर्णय लेने में जनता के व्यापक वर्ग के लिए उपयोगी हो। कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा उनसे संबंधित टिप्पणियां और संबंधित ब्यौरों का उद्देश्य निवेशकों को नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान करने, निवेशित पूंजी पर प्राप्त प्रतिलाभ निर्धारित करने, संबंधित व्यवसाय में चलनिधि का आकलन करने, तथा संबंधित प्रबंधन के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने में सहायता करना है। वित्तीय विवरण वर्ष के अंत में एक कृत्रिम कट-ऑफ लाइन निर्धारित करके तैयार किए जाते हैं, भले ही संबंधित कारोबार लाभकारी संस्थान बना रहे। कई लेनदेनों में किसी लेनदेन का एक चरण पूरा हो गया हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा चरण अभी भी संपन्न न हुआ हो। उदाहरण के लिए कई मुद्दों के संबंध में सवाल उठते हैं, जैसे किसी लेखाकरण अवधि के अंत में न बिके हुए माल का मूल्यांकन लागत-मूल्य पर या वसूली योग्य मूल्य पर किया जाए और स्थायी आस्तियों की लागत के संबंध में लागू होने वाला फार्मूला, तथा ऐसी आस्तियों के मूल्यह्रासित / परिशोधित मूल्य की गणना करने का वैकल्पिक तरीका क्या हो, बहुत-सी आस्तियों/देयताओं का मूल्य कैसे निश्चित किया जाए, दावे और प्रतिदावे, तथा किसी खास लेन-देन का मूल्यांकन करने से जुड़ी अनिश्चितताओं को क्या समझा जाए। इसलिए इन सवालों का हल ढूँढने के लिए उचित लेखाकरण नीतियां तथा लेखाकरण मानक तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।

लेखाकरण मानकों का महत्त्व

4. 'कारोबार की भाषा' के रूप में लेखाकरण, आवधिक वित्तीय विवरणों के जरिए, विभिन्न संबंधित पक्षकारों को किसी उद्यम के वित्तीय परिणाम तथा वित्तीय स्वास्थ्य की जानकारी देता है। किसी दूसरी भाषा की तरह लेखाकरण का भी अपना व्याकरण होना चाहिए तथा ऐसे ही नियमों को लेखाकरण मानक कहते हैं। लेखाकरण मानकों के तीन उद्देश्य हैं। पहला, वे अलग-अलग लेखाकरण नीतियों का मानकीकरण करने में सहायक होते हैं तथा किसी एक संस्था के भीतर और विभिन्न संस्थाओं के बीच वित्तीय विवरणों की तुलना करने में आने वाली जटिलता को दूर करते हैं। दूसरा, वे वित्तीय विवरणों में उच्च गुणवत्ता वाली, पारदर्शी तथा तुलना-योग्य सूचना प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। तीसरा, वे लेखाकरण के विभिन्न विकल्पों में कमी लाते हैं तथा इस प्रकार, वित्तीय विवरणों में व्यक्तिनिष्ठता दूर करते हैं।

*अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग के मानकों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर 11 फरवरी 2011 को प्रह्लाद राय डालमिया लायन्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऐण्ड एकोनॉमिक्स, मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती का भाषण।

5. भारत में लेखाकरण मानक तैयार करने की एक लंबी परंपरा रही है। संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया ने अप्रैल 1977 में एक लेखाकरण मानक बोर्ड गठित किया था तथा यह बोर्ड पिछले 3 दशकों से भारतीय लेखाकरण मानक तैयार करता रहा है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक

6. वित्तीय बाजारों के वैश्वीकरण का मतलब रहा है ''लेखाकरण में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर और अधिक फोकस'' तथा इससे उच्च गुणवत्ता वाले तथा पूरी दुनिया के स्तर पर स्वीकार्य लेखाकरण नियमों / मानकों के एक सेट की ओर अग्रसर होने के प्रयासों में गहनता आई है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग नियमों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का मतलब है - अलग-अलग देशों में अलग-अलग मानक, एक तरह के लेन-देन के बारे में अपने अलग-अलग अर्थ, जिससे अलग-अलग देशों में वित्तीय विवरणों की तुलना करना, उनका विश्लेषण करना तथा उनका मतलब समझना कठिन हो जाएगा।

7. आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ अभिशासन, उच्च गुणवत्ता वाले मानक, तथा दृढ़ विनियामक ढांचे द्वारा समर्थित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। वस्तुतः सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग मानक वित्तीय रिपोर्टिंग सूचना-तंत्र में निवेशकों के विश्वास पर बल देते हैं तथा इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लेखाकरण मानक इस समूची प्रकिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

8. इसी प्ररिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड जैसी स्वंतत्र तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारित करने वाली संस्था की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

क) मानक निर्धारित करने वाली संस्था द्वारा, अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले, समझ में आने लायक, लागू करने योग्य और विश्व स्तर पर मान्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का एक सेट विकसित/ तैयार किया जाना;

ख) उन मानकों के प्रयोग तथा विधिवत अनुपालन को बढ़ावा देना;

ग) उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों तथा छोटे और मझोले आकार वाली संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना; और

घ) राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों में सामंजस्य स्थापित करके उच्च गुणवत्ता वाले समाधान तैयार करना।

9. वैश्विक लेखाकरण मानकों की ओर अग्रसर होना, यथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमों के बीच तुलना के काम को सुगम बनाते हैं। इस प्रकार वैश्विक लेखाकरण मानक पूंजी प्रवाह के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेंगे तथा बाजारों में ज्यादा तथा दीर्घावधिक निवेश को बढ़ावा देंगे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की ओर बढ़ना उद्योग जगत के हित में भी है क्योंकि उनका अनुपालन करने से निवेशकों के मन में और अधिक आत्मविश्वास पैदा होगा तथा विदेशी पूंजी की उगाही करने की लागत में कमी आएगी। अलग-अलग देशों के अलग-अलग लेखाकरण मानकों का अनुपालन करना तथा सामूहिक रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए एक मानक में उन्हें रूपांतरित करना, अलग-अलग देशों में काम करने वाले उद्यमों के लिए बोझिल तथा अधिक लगत वाला होगा। अलग-अलग मानकों में सांमजस्य स्थापित करने से उद्योग-जगत के लिए पूंजी की लागत और अनुपालन की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी।

10. अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड अपने उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए पूरी दुनिया में निवेशकों, राष्ट्रीय मानक-निर्धारकों, विनियामकों, लेखा-परीक्षकों, शिक्षाविदों तथा उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक मानक विकसित करने में रुचि रखने वालों के साथ मिलकर सभी पक्षकारों के निकट सहयोग से काम करता रहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति संबंधी गतिविधियां बहुत अच्छी रही हैं। सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की ओर अग्रसर होने या उन्हें पूर्णतः स्वीकार करने के लिए एक समय-सीमा निश्चित कर रखी है तथा 100 से अधिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रयोग को अनुमति भी दे दी है।

11. यद्यपि भारतीय लेखाकरण मानक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मानकों को आधार बनाकर तैयार किए गए हैं, फिर भी हमारे देश के कानूनी और विनियामक परिवेश, सैद्धांतिक मुद्दों तथा आर्थिक परिवेश के कारण उनमें कुछ अंतर भी हैं। वर्ष 2007 में इंडियन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया ने निश्चय किया कि अन्य प्रमुख क्षेत्रों में हो रही प्रमुख गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत को भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की ओर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि अन्य प्रमुख क्षेत्रों ने भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को अपनाने के लिए समय-सीमा निश्चित कर रखी है।

वित्तीय संकट से प्राप्त सीख

वित्तीय लिखतों संबंधी मानकों की समीक्षा

12. वैश्विक वित्तीय संकट का सबसे बड़ा अस्थिर करनेवाला एक तथ्य बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय बाजारों और व्यापक अर्थव्यवस्था के माध्यम से वित्तीय आघातों में हुई अनुचक्रीय भारी वृद्धि रहा है। अनुचक्रीय आधार पर व्यवहार करने की बाजार के भागीदारों की प्रवृत्ति में कई चैनलों से व्यापक वृद्धि हुई है जिनके अंतर्गत, 'मार्क टु मार्केट आस्तियों' तथा 'हेल्ड टु मेच्युरिटी ऋणों ' (दोनों) के लिए निर्धारित लेखाकरण मानक, मार्जिन संबंधी प्रथाएं और वित्तीय संस्थाओं, फर्मों और उपभोक्ताओं के बीच लिवरेज में व्यापक वृद्धि तथा लिवरेज के उन्मोचन शामिल हैं। बैलेंस शीट में शामिल तथा बैलेंस शीट से इतर प्रमुख जोखिमों पर नियंत्रण न रख पाना तथा डेरिवेटिवों से संबंधित ऋण आदि जोखिम भी अस्थिरता पैदा करने वाले प्रमुख कारक थे।

13. अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड द्वारा जारी किए गए 'आइएएस 39 - वित्तीय लिखत - मान्यता और माप' के प्रावधानों के अंतर्गत, वित्तीय अस्तियों और वित्तीय देयताओं को स्वीकार करने तथा उनकी माप करने के सिद्धांत तय किए गए हैं। यह मानक बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय लिखतों संबंधी प्रमुख कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विशेष महत्त्व का है। आइएएस-39 के अंतर्गत वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण, उनकी निरंतर माप, उनके मूल्य में कमी लाया जाना कब अपेक्षित है, के अलावा उनकी मान्यता समाप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। आइएएस-39 के प्रावधान इस समय वित्तीय लिखतों के मामले में वैश्विक स्तर पर लागू हैं।

14. वित्तीय संकट के बाद बड़ी आलोचना यह की जा रही थी कि लेखाकरण संबंधी मानकों, और उनसे भी अधिक, अच्छी गुणवत्ता वाले लेखाकरण मानकों ने वित्तीय संकट बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान किया, या कम-से-कम वित्तीय संकट की गंभीरता में तीव्रता लाने का काम किया क्योंकि ये मानक नकदी की कमी झेल रहे बाजारों तथा बिक्री में भारी कमी की स्थिति से गुजरने वाले बाजारों को उबारने में असफल रहे।

15. 'स्वस्थ विनियमन संवर्धन और पारदर्शिता सुदृढ़कीरण' के लिए जी-20 देशों द्वारा गठित किए गए कार्यदल ने यह सिफारिश की थी कि लेखाकरण मानक निर्धारित करने वालों को ऐसी ऋण-हानियों को स्वीकार करने तथा उनकी माप करने के वैकल्पिक उपायों पर विचार करके ऋण-हानि संबंधी प्रावधानों को लेखांकन की दृष्टि से स्वीकार करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना चाहिए जिनके अंतर्गत ऋण संबंधी व्यापक सूचना समाहित होनी चाहिए। जी-20 देशों के कार्यदल ने यह सिफारिश की थी कि अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड को, इस प्रक्रिया को पूर्ण कर चुकने वाले देशों के अनुभवों से लाभ उठाकर और तकनीकी सहायता प्रदान करके, वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले एक लेखाकरण मानक की ओर अग्रसर होने के काम को सुकर बनाने के और अधिक प्रयास करने चाहिए। एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि लेखाकरण मानक-निर्धारकों को वित्तीय लिखतों संबंधी लेखाकरण मानकों की जटिलताओं को कम करने के प्रयासों को तेज करना चाहिए और वित्तीय लिखतों के मूल्यांकनों से जुड़ी अनिश्चितताओं का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय विवरणों का प्रयोग करने वालों के लिए प्रस्तुतीकरण संबंधी मानकों में और सुधार लाना चाहिए।

16. अप्रैल 2009 में अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड ने, वित्तीय संकट का सामना करने के लिए किए गए अपने काम के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया के उत्तरस्वरूप तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सिफारिशों के बाद, वित्तीय लिखतों की मान्यता और माप संबंधी प्रधान मानक - आइएएस-39 को बदलने के लिए एक त्वरित समय-सारणी की घोषणा की। आइएएस-39 को हटाकर उसकी जगह तीन चरणों में आइएफआरएस-9 लाए जाने का प्रस्ताव है। आइएफआरएस-9 के उस भाग को जारी करके पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया है जिसमें वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के वर्गीकरण तथा उनकी माप के संबंध में मानक तय किए गए हैं। दूसरे और तीसरे चरण "हेज अकाउन्टिंग" तथा "आस्तियों में आने वाली हानि" से संबंधित हैं जिनसे संबंधित काम अभी चल रहा है। आशा है कि जून 2011 तक आइएएस 39 के स्थान पर आइएफआरएस-9 पूरी तरह काम करने लगेगा।

आइएफआरएस अपनाना - भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन तथा चुनौतियां

17. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गतिविधियों की पृष्ठभूमि में कंपनी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) ने आइएफआरएस के प्रभावों का अध्ययन करने तथा आइएफआरएस लागू करने के मामले में भारतीय कंपनियों की तैयारी को समझने के लिए, कंपनी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार-प्राप्त कार्यदल गठित किया। कंपनी कार्य मंत्रालय ने, कंपनियों द्वारा 1 अप्रैल 2011 से आइएफआरएस अपनाने के लिए संबंधित कार्य-योजना को जनवरी 2010 में अंतिम रूप दे दिया है।

18. आइएफआरएस अपनाए जाने के काम के साथ, हमारे देश की कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के साथ उसका तालमेल बिठाए जाने का काम भी जुड़ा है। इसके लिए वर्तमान कानूनों और विनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम 1956 के वे प्रावधान तथा अनुसूचियां शामिल हैं जिनमें वित्तीय विवरणों संबंधी अपेक्षाओं का ब्यौरा दिया गया है जिनका आइएफआरएस की अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाया जाना और नए भारतीय लेखाकरण

मानकों का उस अधिनियम की धारा 211 (3 सी) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना जरूरी है। इसके अलावा, आइएफआरएस अपनाए जाने के बाद के परिवेश में कराधान से जुड़े मुद्दों का भी समाधान किया जाना है।

19. आइएफआरएस संबंधी लेखाकरण और लेखा-परीक्षा प्रोफेशन के लिए तकनीकी क्षमता तैयार करने और सामान्यतः जागरूकता में वृद्धि किए जाने की भी जरूरत है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल ऐडवान्स अकाउंटेंसी के पाठ्यक्रम में भारतीय लेखाकरण मानकों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के तुलनात्मक अध्ययन को पहले ही शामिल कर लिया है तथा इस मामले में अपने सदस्यों की जानकारी को अद्यतन बनाए रखने के लिए अन्य पाठ्यक्रमों और सेमिनारों की व्यवस्था कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक भी अपने स्टाफ सदस्यों को आइएफआरएस के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए समय-समय पर सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए चुनौतियां

20. बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित खास मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए आइएफआरएस-9 को 2011 के मध्य तक अंतिम रूप दे दिये जाने की उम्मीद है। बैंकिंग उद्योग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आइएफआरएस अपनाने हेतु मार्च 2010 में एक अलग कार्य-योजना तैयार की गई। आइएफआरएस-9 अपनाए जाने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2013 से शुरू होगी जिसके अंतर्गत शहरी बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए चरणबद्ध प्रक्रियाएं अपनायी जाएँगी। इससे सुव्यवस्थित तरीके से तथा बिना किसी बड़े व्यवधान के, इन मानकों को अपनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली को थोड़ा समय मिल जाएगा।

21. लेकिन यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आइएएस-39 हटाए जाने और वित्तीय लिखतों, उचित मूल्य-मापन, वित्तीय विवरण की प्रस्तुति तथा समेकन सहित लेखाकरण संबंधी अन्य विभिन्न गतिविधियों के कारण बैंकों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख परिवर्तन वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण और मापन, आस्तियों के मूल्य में कमी लाए जाने संबंधी प्रावधानों और उचित मूल्य-मापन जैसे कुछ अतिमहत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। एक बड़ी चिंता का क्षेत्र आइएएस-39 के ''उपगत हानि मॉडल'' की कमियों तथा और अधिक अग्रगामी प्रावधानीकरण लागू किए जाने की आवश्यकता से जुड़ा है।

22. आइएफआरएस अपनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतः बैंकिंग प्रणाली के लिए बड़ी चुनौतियां शामिल होंगी। आइएफआरएस से जुड़ी जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन सहित अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की जरूरत होगी। आइएफआरएस अपनाने की प्रक्रिया के दौरान भारतीय बैंकों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख तकनीकी कठिनाइयों के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण तथा मापन संबंधी वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों और आइएफआरएस से संबंधित मानकों के बीच का अंतर, बैंकों द्वारा अपनाए गए कारोबारी मॉडल संबंधी मानकों पर फोकस और इससे जुड़े क्षेत्र का प्रबंधन, ऐसे लेन-देन के मामले में उचित मूल्यनिर्धारण/मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करना जिनके संदर्भ में भारत में बाजार की प्रथाओं या बेंचमार्कों की दृष्टि से अधिक दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, और आस्तियों के मूल्य में कमी लाए जाने के मामले में अपेक्षित परिवर्तन, शामिल हैं।

लेखाकरण से भिन्न अन्य प्रमुख मुद्दे

23. मैं आपका ध्यान लेखाकरण से भिन्न कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो आइएफआरएस अपनाने की प्रक्रिया में बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। लेखाकरण संबंधी मुद्दों के साथ-साथ यदि लेखाकरण से भिन्न इन मुद्दों का समाधान न किया जाए तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। पहली चुनौती आंकड़ों और सूचना में सच्चाई है। भारत स्थित अधिकांश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने या तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पहले ही अपना लिया है या वे उसे अपनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आइएफआरएस के अनुरूप तैयार कर लिए गए मानकों की आंकड़ा-गहन अपेक्षाओं के कारण आंकड़ों की सच्चाई तथा आंकड़ों की वैधता अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगी। आंकड़ों के समेकन तथा प्रस्तुतीकरण की वर्तमान प्रणाली, जो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, के अंतर्गत आंकड़ों की गुणवत्ता से समझौता कर लिया जाता है। गलत आंकड़ा-प्रविष्टि या विद्वेषणूर्ण गलत रिपोर्टिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के परिणामस्वरूप, गतिविधि के स्तर पर 'प्रतिलाभ' के संबंध में और छोटे-छोटे खंडों में अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्टिंग के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती। प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों के ऑटोमेटेड प्रवाह/जनरेशन के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में उपयुक्त क्षमता का प्रावधान करने से सही-सही रिपोर्टिंग में सुगमता आएगी तथा ऐसे आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों से किसी संस्था की वित्तीय स्थिति की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस संबंध में काम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक कार्यदल गठित किया है। इस मामले में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्य से, आइएफआरएस की ओर अग्रसर होने के हमारे प्रयासों के मार्ग में आने वाली आधारभूत चुनौतियों से निपटने में हमें सहायता मिलेगी।

24. दूसरा, हम अब ''नैतिक मानकों'' की बात करेंगे जो लेखाकरण के क्षेत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, जहां प्रयोक्ता लेखाकरण के प्रोफेशनल्स द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। नीति संबंधी सुदृढ़ कोड तथा नीति संबंधी विनियमों के कड़ाई से पालन के अभाव में किसी भी संस्था में जनता और निवेशकों का विश्वास नहीं बन सकेगा। इस प्रकार, उच्च स्तर की तकनीकी क्षमता के साथ-ही, लेखाकरण का काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए निर्विवाद और दोषरहित /स्वच्छ प्रोफेशनल-निष्ठा की भी नितांत आवश्यकता होगी। इसलिए प्रोफेशनल संस्थाएं अपने सदस्यों के लिए नैतिक संहिता तैयार करती हैं और जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध की जानेवाली अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी तैयार करती हैं। फिर भी, हाल के वित्तीय संकट का एक कारण लेखाकरण का काम करने वाले कुछ प्रोफेशनल्स द्वारा नीति संबंधी इन नियमों का कड़ाई से पालन न किया जाना था क्योंकि इन प्रोफेशनल्स ने अपनी वित्तीय स्थिति संबंधी कमजोरियों को छिपाने तथा गलत तरीके से लाभ दिखाने के लिए 'वास्तविक स्थिति की तुलना में प्रणाली के स्वरूप' का अनुचित तरीके से लाभ उठाया।

25. तीसरा, बैंकों द्वारा इस समय प्रयोग में लए जा रहे आईटी समाधानों का, आइएफआरएस अपनाने के बाद पैदा हुई नयी अपेक्षाओं के अनुसार अनुकूलन करना तथा उन्हें संगत बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जो सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं, उनमें आइएफआरएस की अपेक्षाओं के अनुसार नयी विशेषताओं को शामिल करते हुए पर्याप्त संशोधन किए जाने की जरूरत होगी। उसी प्रकार नयी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संगति बिठाए जाने की जरूरत होगी।

26. रिज़र्व बैंक का हमेशा यह विश्वास रहा है कि लेखाकरण संबंधी मानकों और उनके कार्यान्वयन में ईमानदारी की वित्तीय प्रणाली में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जैसा कि वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है जिसमें भारत के लेखाकरण संबंधी मानकों के आइएफआरएस की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया के महत्त्व पर बहुत जोर दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने इंडियन चार्टर्ड अकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक संघ और रिज़र्व बैंक के विनियामक तथा पर्यवेक्षी विभागों के सदस्यों को शामिल करके एक कार्यदल गठित किया है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के आइएफआरएस की ओर सुचारुरूप से तथा व्यवधान-रहित तरीके से अग्रसर होने / उसके कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों / समस्याओं का समाधान करेगा।

निष्कर्ष :

27. आइएफआरएस के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण, शिक्षण और कौशल-विकास आधार स्तंभ हैं। निवेशकों, लेखाकारों / लेखा-परीक्षकों, ग्राहकों, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर विक्रेताओं, रेटिंग एजेंसियों, विश्लेषकों, लेखा-परीक्षा समितियों, बीमा-जोखिम और प्रीमियम निर्धारकों, मूल्यांकन के विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित हितधारियों के लिए आइएफआरएस के प्रावधानों की समझ, अलग-अलग स्तर तक, विकसित करने की जरूरत होगी, तथा यह भी समझने की जरूरत होगी कि उन्हें क्या करना है। शिक्षा संस्थाओं को एक अग्रसक्रिय भूमिका निभानी होगी तथा छात्रों को भी नए ढांचे के विभिन्न पहलुओं तथा सिद्धांतों को भलीभांति समझने के लिए प्रयास करना होगा। शिक्षा संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम में इन बातों का समावेश करना होगा। हम आइएफआरएस की ओर कितनी सफलतापूर्वक अग्रसर होते हैं, यह इस बात से निर्धारित होगा कि हम लेखाकरण संबंधी मुद्दों के साथ-साथ लेखाकरण से भिन्न मुद्दों का भी किस तरह समाधान करते हैं। इस पृष्ठभूमि में, तथा विश्व स्तर पर और भारतीय संदर्भ में इन मानकों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों पर विचार करते हुए - तथा आइएफआरएस अपनाने में लगने वाले प्रयासों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आइएफआरएस विषय पर आयोजित किया गया यह सेमिनार अत्यंत महत्त्वपर्ण हो जाता है। मैं इस सेमिनार में होने वाले विचार-विमर्श की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।